शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार में
मध्यप्रदेश

1 जून से स्कूल-कॉलेज, धर्मस्थल खोलने की छूट संभव

रणनीति पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की

देश में 68 दिन का लॉकडाउन रविवार को खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर लॉकडाउन 4.0 के बाद की रणनीति पर चर्चा की। शाह ने मुख्यमंत्रियों से मिले सुझाव भी प्रधानमंत्री को बताए। केंद्र के अधिकारियों के अनुसार, 1 जून के बाद लॉकडाउन करीब दो हफ्ते बढ़ सकता है। लेकिन, इसमें पाबंदियां तय करने में केंद्र की भूमिका बेहद सीमित रहेगी। रियायतें बढ़ाने-घटाने का अधिकार पूरी तरह राज्यों को देने की तैयारी है।

सूत्रों के अनुसार, राज्य 1 जून से शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल और रेस्तरां खोलने या मेट्रो ट्रेन शुरू करने पर फैसला ले सकेंगे। हालांकि, कहीं भी प्रवेश के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और आरोग्य सेतु एप अनिवार्य किए जाएंगे। केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के साथ ही देशभर में मॉल और सिनेमा हॉल बंद रखने का आदेश दे सकती है। अधिकारियों के अनुसार, हर 15 दिन में लॉकडाउन की समीक्षा होगी। इसमें भी स्थानीय हालात के अनुसार राज्य फैसला लेंगे। सूत्रों ने बताया कि राज्यों के फीडबैक के आधार पर गृह मंत्रालय लॉकडाउन के अगले चरण की गाइडलाइंस बनाने में जुटा है।

कर्नाटक के बाद बंगाल में भी धर्मस्थल खोलने का फैसला

प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से राज्य में धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों में पूरी संख्या में कर्मचारी जा सकेंगे। ये फैसले ऐसे समय में आए हैं, जब श्रमिकों की वापसी के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस करार दिया। ममता से पहले कर्नाटक सरकार भी राज्य में 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने का फैसला कर चुकी है। वहीं, केरल में भी धर्मगुरुओं ने मंदिर, मस्जिद और चर्च खोलने का आग्रह किया है।

सबसे ज्यादा मरीजों वाले 30 शहरों पर फोकस : नई गाइडलाइंस में केंद्र का जोर सिर्फ कंटेनमेंट जोन पर रह सकता है। यहां संक्रमण रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी। देश के कुल 30 नगर निगम क्षेत्रों में देशभर के 80% से ज्यादा मरीज हैं। इनमें से 13 शहरों के अधिकारियों के साथ गुरुवार को कैबिनेट सचिव ने भी बैठक की थी। 1 जून से नगर निगम ही तय कर पाएंगे कि किसी आवासीय कॉलोनी, मोहल्ला, वार्ड या पुलिस थाना क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना है या नहीं।

मप्र और रियायत मांगेगा, सुझाव पर बैठक आज

पॉलिटिकल रिपोर्टर. भोपाल | लॉकडाउन 5.0 का स्वरूप मप्र में कैसा हो, इसे लेकर राज्य सरकार शनिवार को बैठक करने जा रही है। इसके बाद ही राज्य सरकार केंद्र सरकार को सुझाव भेजेगी। यहां बता दें कि कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से लॉकडाउन 5.0 को लेकर सुझाव मांगे हैं। लॉकडाउन 4.0 में मप्र ने ऑरेंज जोन का वर्गीकरण खत्म कर दिया था। सिर्फ रेड जोन और ग्रीन जोन ही रखे थे। रेड जोन में इंदौर और उज्जैन का पूरा जिला है, जबकि भोपाल समेत 9 नगरीय निकाय रेड जोन में रखे गए थे। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन 5.0 में राज्य और रियायत मांग सकते हैं। हालांकि मप्र के तकरीबन सभी जिलों में पॉजिटिव केस मिल गया है। विशेषज्ञों की राय है कि जून-जुलाई में कोरोना के केस और बढ़ेंगे, इसलिए इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए मप्र अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेजेगा।

जुगाड़... डिब्बे और गिलास का ले रहे सहारा

स्कूलों में नहीं हैं तराजू और बाट शिक्षक अंदाज से बांट रहे अनाज

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्राइमरी व मिडिल कक्षाओं के छात्रों को मध्यान्ह भोजन के लिए स्कूल से अनाज का वितरण किया जा रहा है। कोरोना की वजह से स्कूलों में भोजन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए छात्रों को गेहूं और चावल दिया जा रहा है, लेकिन अनाज वितरण के लिए जो वजन निर्धारित किया गया है, उसे तौलने के लिए ज्यादातर स्कूलों में तराजू-बाट की व्यवस्था नहीं है। अनाज वितरण 1 मई से 15 जून तक की अवधि का किया जा रहा है। स्कूलों में तराजू न होने से शिक्षक डिब्बे या गिलास से अंदाजन अनाज छात्रों को वितरित कर रहे हैं। हालांकि, कुछ जगह शिक्षकों ने आसपास के लोगों के सहयोग से वेगिंग मशीन की व्यवस्था भी कर ली है। छात्रों को अनाज देने के लिए उन्हें पास की सरकारी राशन की दुकान से गेंहू-चावल लाना पड़ रहा है।

परेशानी...राशन दुकान से लाते हैं गेहूं-चावल

शिक्षकों ने बताया कि ज्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में आ रही है। कंट्रोल की दुकान से वे गेहूं-चावल लाते हैं। इसमें स्व-सहायता समूह भी मदद करते हैं, लेकिन उनके पास अनाज तौलने की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को 3 किलो 600 ग्राम गेहूं और 4 किलो 300 ग्राम चावल वितरण किया जा रहा है। नमक, तेल-मसाले के लिए मिडिल के छात्रों के खाते में 221 व प्राइमरी के छात्रों खातों में 148 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। शिक्षकों के मुताबिक तराजू न होने की स्थिति में वे संबंधित माप के डिब्बे का उपयोग कर रहे हैं। अगर किसी डिब्बे में दो किलो अनाज आ जाता है तो उससे माप लेकर अनाज दे दिया जाता है। ऐसे में निर्धारित माप में थोड़ा-बहुत अंतर आ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शिक्षक छात्रों के घर भी सीधे अनाज पहुंचा रहे हैं।

जो भी समस्या आ रही है, दूर की जाएगी

शिक्षक अनाज के पैकेट बनाकर दे रहे हैं। हमने दो अधिकारी भी औचक निरीक्षण के लिए लगाए हैं। जहां से अनाज मिलता है वहां जरूर तुलाई की शिकायतें मिली हैं। जो भी समस्या है उसे दूर करवाएंगे।

- नितिन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल

शिक्षक बीमा बचत योजना से जुड़े आदेश पर तारीख की गलती मानी विभाग ने

इंदौर। नवीन शिक्षक संवर्ग को समूह बीमा योजना का लाभ देने से जुड़े आदेश के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी गलती मान ली है। अवर सचिव आरके डेकाट ने 27 मई को आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र लिखा है कि आदेश में 27 जुलाई 2020 को 27 जुलाई 2019 ही पढ़ा जाए। उप सचिव ने 22 मई को आयुक्त के नाम आदेश जारी किया था। इसमें शैक्षणिक संवर्ग यानी राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में शामिल किए गए अध्यापकों को समूह बीमा सह बचत योजना-2003 का लाभ देने की बात कही गई है। विभाग ने इस बारे में पूर्व में जारी आदेश का हवाला दिया है। संदर्भित पत्र जारी करने की जो तारीख दी है, वह 27 जुलाई 2020 है। हकीकत में यह पत्र 27 जुलाई 2019 को जारी हुआ था। डीबी स्टार ने यह मामला 24 मई को में प्रकाशित किया था। इसके बाद अफसर गंभीर हुए और अब लोक शिक्षण संचालनालय को सही तारीख के बारे में पत्र लिखा है। पत्र में लिखा कि बीमा सह बचत योजना 2003 का लाभ देने के संबंध में 22 मई को जारी आदेश के संदर्भित पत्र क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 में 27 जुलाई 2020 को 27 जुलाई 2019 पढ़ा जाए।

ड्यूटी कोरोना संक्रमण रोकने की, पर भी शिक्षकों को योद्धा नहीं मानता शासन

मध्य स्वदेश ■ गाडरवारा

जहां एक और पूरे देश में और मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है वहीं गाडरवारा तहसील में शिक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ड्यूटी लगाई गई है। गाडरवारा तहसील की अस्पताल मे शिक्षकों को हेल्प डेस्क पर ड्यूटी लगाई गई है। सभी शिक्षक पूरी मनोयोग से अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं जिनकी पारी सुबह 6 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक दो 2 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है वहीं पर चेक पोस्ट कामती झिकोली ककराघाट पनागर और कंट्रोल रूम मे शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी शिक्षक अपने कार्य का निर्वहन पूर्ण सहयोग से कर रहे हैं। वही गाडरवारा अस्पताल में आनंद चोकसे सुरेन्द्र पटैल, उमाकांत पचोरी, प्रसन्न दुबे, पुरुषोतम मेहरा, मनोहर लाल कीर की ड्यूटी गई लगाई है अब सिर्फ गाडरवारा अस्पताल में ही शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। बाकी सभी अस्पतालों को रिजर्व सेंटर घोषित कर दिया गया है जब बाकी अस्पतालों में ड्यूटी की आवश्यकता होगी तब शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी और कई. चेक पोस्ट और कोरेनटाइन सेन्टर भी रिजर्व कर दिये गये है लेकिन कोरोना योद्धा सिर्फ सफाईकर्मी, डॉक्टर, पुलिस को माना जा रहा है जबकि स्थलों पर ड्यूटी शिक्षकों, आंगनवाड़ी नगरपरिषद, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोतवाल पटवारी और अन्य विभाग भी शामिल है । आखिर ये कैसी नीति नियम जो कार्य करने वालो में भी अंतर कर रहे है।

स्कूली बच्चे पढ़ेंगे कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा के उपाय

12वीं कक्षा तक की पुस्तक में छपेंगे जागरूकता संदेश

भोपाल

अब प्रदेश के स्कूलों के बच्चे कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने एक पहल की है। इस वायरस से संबंधित सुरक्षा के उपाय को पाठ्यपुस्तकों में संदेश के रूप में शामिल किया जा रहा है। अगले सत्र से पहली से लेकर 12वीं तक की सभी विषयों की किताबों में दो पेज का संदेश जोड़ा जाएगा। इस सत्र से सिर्फ 9वीं और 11वीं के बच्चे इस संदेश को पढ़ पाएंगे, क्योंकि दोनों कक्षाओं की भाषा की किताबों की छपाई अभी नहीं हुई है। जबकि अन्य सभी कक्षाओं की किताबें छपकर तैयार हो गई हैं। इसमें पहले पेज में कोविड-19 से बचाव के उपाय और दूसरे पेज में शाला स्वच्छता और सुरक्षा को शामिल

किया गया है। वहीं, अगले सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) चीनी वायरस के विषय में जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रहा है। अभी तक स्कूलों में जीवविज्ञान के पाठ्यक्रमों में एड्स, मलेरिया, स्वाइन लू, हेपेटाइटिस-बी, हैजा और अन्य रोग-वायरस के बारे में विद्यार्थी पढ़ते हैं।

9वीं व 11वीं की भाषा की किताब अभी नहीं छपी

राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी ने बताया कि इस सत्र से 9वीं व 11वीं में भाषा की किताबें एनसीईआरटी की ली जा रही हैं। इस कारण राज्य शिक्षा केंद्र को एनसीईआरटी से दोनों विषयों की सीडी देर से मिली, जिससे दोनों विषयों की किताबें अभी छप नहीं पाई। अब दोनों विषयों की किताबों में संदेश को इस बार से ही प्रकाशित किया जाएगा।

'श्रेष्ठ पांच हजार योजना' देगी श्रमिकों के बच्चों को संबल

दसवीं-बारहवीं में राज्य की प्रावीण्य सूची में आने वाले पांच हजार बच्चों को मिलेंगे पच्चीस हजार रुपए

भोपाल

प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक बार फिर श्रमिक हितैषी योजनाएं शुरू हो रही हैं। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के पंजीबद्ध श्रमिकों के दसवीं और बारहवीं में अध्ययनरत बच्चों के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण सुपर पांच हजार संबल योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में विभिन्न संकायों की प्रावीण्य सूची में पहले पांच हजार स्थान पर रहे बच्चों को राज्य सरकार पच्चीस हजार रुपए की मदद करेगी।

श्रम विभाग इस योजना का संचालन करेगा। इस योजना के तहत पंजीबद्ध असंगठित कामगार की ऐसी संतान जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय अथवा स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करते हुए संपूर्ण राज्य की प्रावीण्य सूची में अपने संकाय के सर्वोच्च पांच हजार बच्चों में शामिल होगा, उन्हें आगे अध्ययन जारी रखने के लिए राज्य सरकार एकमुश्त एक बार में पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री जनकल्याण

संबल योजना के अंतर्गत वैध परिचय पत्र धारी असंगठित श्रमिक के पुत्र अथवा पुत्री इस योजना के लिए पात्र होंगे। जिले में पदस्थ सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी एवं सहायक श्रम पदाधिकारी इस योजना का संचालन करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे वे ही चयन और राशि की अंतिम रूप से मंजूरी प्रदान करेंगे।

ऐसे होगा चयन

पात्र हितग्राही माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के प्रमाण-पत्र सहित संबंधित विद्यालय जहां से दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण की है वहां के प्राचार्य को इसके लिए आवेदन करना होगा। वहां से अनुशंसा प्राप्त होने पर संबंधित जिले के अधिकृत श्रम विभाग के पदाविहित अधिकारी द्वारा जांच के पश्चात पात्र पाए जाने पर हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। श्रम विभाग के अधिकारी प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर इसे जनकल्याण पोर्टल पर दर्ज करेंगे और पोर्टल के माध्यम से ही मंजूरी प्रदान की जाएगी। पोर्टल पर स्वीकृत प्रकरणों में ईपीओ जनरेट किया जाएगा। इसके आधार पर प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे हितग्राही के खाते में अंतरित की जाएगी।

विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए विशेषज्ञों के साथ मिलकर आयोग ने तैयार किया एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर

विभाग कर रहा जुलाई में स्कूल खोलने पर विचार, बाल आयोग सितंबर माह के पक्ष में, भेजी सुरक्षा गाइडलाइन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

कोरोना संक्रमण और एहतियात के तौर पर लागू किए लॉकडाउन में लगभग ढाई माह से स्कूल बंद हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग सामान्य स्थिति होने पर 15 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग गंभीर है। वहीं बाल आयोग जुलाई की बजाए सितंबर से स्कूल खोले जाने के पक्ष में है। आयोग ने उसी वक्त के हिसाब से विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी इसे लेकर विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय की है और इस गाइड लाइन को शिक्षा विभाग को भेजा है।

खास बातें

- एहतियात के तौर पर करीब ढाई माह से बंद है सभी स्कूल
- 55 सीटर बसों में 20 से 25 बच्चे होंगे वहीं छोटी बसों में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए बैठाना होगा

प्राइमरी स्कूल के बच्चों को न बुलाया जाए

गाइड लाइन में बच्चों के घर से निकलने से लेकर स्कूल बस, स्कूल और टीचर्स और घर पहुंचने पर अभिभावकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है। आयोग सदस्य राजेश चौहान ने बताया कि शिक्षा विभाग के जरिए इस गाइड लाइन पर स्कूलों का पक्ष भी जानने के बाद इसे अंतिम रूप से पूरी प्रक्रिया तय कर लागू किया जाएगा। चौहान ने कहा कि हम सितंबर के पूर्व स्कूल खुलने के पक्ष में नहीं हैं और इस दौरान भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को न बुलाया जाए। आयोग का मानना है कि स्कूल सभी प्रकार से सुरक्षित होने बाद ही शुरू करने हेतु अनुमति दी जाए। साथ ही यह अनुमति आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुकूल होने पर दी जाए।

अभिभावकों को भी रखना होगा ध्यान, सर्दी-जुकाम होने पर बच्चे को न भेजें

गाइडलाइन में पालकों से बच्चे के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जानकारी देने और हल्का सा सर्दी-जुकाम होने पर भी उसे स्कूल ना भेजने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पालकों के लिए निर्देश है कि वे कोविड-19 सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का पालन करते हुए ही बच्चे को स्कूल भेजें।

बसों को अलग-अलग गेट से प्रवेश कराया जाए

गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि यदि स्टूडेंट बस से स्कूल जाता है तो 55 सीटर बसों में 20 से 25 बच्चे होंगे वहीं छोटी बसों में 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए छात्रों को बैठाना होगा, मुख्य रूप से दो गज की दूरी का ध्यान रखना जरूरी होगा। बच्चों को डायरेक्टरेट की ओर से निर्धारित स्टैंडर्ड कंटेट के सेनिटाइजर से सेनिटाइज बस में ही बैठाया जाएगा। इसके अलावा बसों को स्कूल के अलग-अलग गेट से प्रवेश कराया जाए, जिससे बच्चों की भीड़ जमा ना हो। स्कूल को भी पूरी तरह हर दिन सेनिटाइज करना आवश्यक होगा। कक्षाओं में लगे फर्नीचर छह फीट की दूरी पर लगे हों एवं पूर्णतः सेनिटाइज हों। दरवाजे, खिड़की, गेट के हैंडल और मेटल के सामान अच्छे से धोएं। स्कूल में पीने और हाथ धोने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो और हर पीरियड के बाद बच्चों के हाथ धुलवाएं। इसके साथ ही गाइड लाइन में यह भी कहा गया है कि कोविड के खतरे को देखते हुए स्कूल में यूनिफार्म को अनिवार्य न रखा जाए, जिससे बच्चा हर दिन साफ धुले कपड़ों में स्कूल पहुंच पाए।

बगैर 2 एफ, 12बी की मान्यता के चल रहे 5 सरकारी महाविद्यालय

नैक मूल्यांकन सम्भव नहीं, फिर भी उच्च शिक्षा विभाग निरंतर दे रहा निर्देश

जागरण, रीवा। जिले के 5 सरकारी महाविद्यालयों के पास 2एफ और 12 बी की मान्यता नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तय मान्यता न होने पर संबंधित महाविद्यालयों का नैक मूल्यांकन नहीं हो सकता। फिर भी उच्च शिक्षा विभाग ऐसे सभी महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन कराने हर माह निर्देशित कर रहा है। संबंधित महाविद्यालयों के पास स्वयं का भूमि-भवन, नियमित स्टॉफ व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर न होने पर उक्त मान्यता नहीं है। लिहाजा सरकार ऐसे महाविद्यालयों को मूलभूत सुविधा देने के बजाये हर साल नये महाविद्यालय खोलने की घोषणा करती जा रही है।

गौरतलब है कि अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय रीवा अंतर्गत 71 सरकारी महाविद्यालय हैं। रीवा जिले में 16 सरकारी महाविद्यालय हैं, जिनमें से 5 महाविद्यालयों के पास भूमि-भवन नहीं है। ऐसे ही एडी रीवा अंतर्गत भूमि-भवन विहीन सरकारी महाविद्यालयों की संख्या 30 है। इन सभी महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधा न होने से शैक्षणिक गुणवत्ता खासी प्रभावित हो रही है। लिहाजा ऐसा भी प्रतीत होता है कि सरकार ने इन महाविद्यालयों को सिर्फ कागज में दिखाने के लिए खोला है।

बैठकें सिर्फ कागजों तक सीमित

विगत माह उच्च शिक्षा विभाग की एक बैठक भोपाल में हुई। विभाग के मुखिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी नैक मूल्यांकन संबंधी चर्चा हुई। बैठक में सभी महाविद्यालयों की एसएसआर रिपोर्ट नैक बोर्ड भेजने के लिए कहा गया। अब चूंकि भूमि-भवन विहीन महाविद्यालयों के पास 2एफ और 12बी की मान्यता ही नहीं है। ऐसे में वह नैक बोर्ड को एसएसआर रिपोर्ट भेजने की पात्रता ही नहीं रखते। फिर भी वरिष्ठ अधिकारी इन कमियों की अनदेखी सालों से करते आ रहे हैं। हाल ही में विभाग ने सभी कॉलेजों को 2एफ और 12बी की मान्यता के लिए यूजीसी के समक्ष आवेदन भी करने के लिए कहा है। विभाग के इस निर्देश का पालन करने में भी कॉलेज प्रबंधन हिचक रहे हैं।

जिले के इन महाविद्यालयों का बुरा हाल

रीवा जिले में शासकीय महाविद्यालय मनगवां को 2एफ, 12बी की मान्यता नहीं है। हालाकि महाविद्यालय प्रबंधन को हाल ही में जिला प्रशासन ने 5 एकड़ भूमि आवंटित की है। इसी तरह शासकीय महाविद्यालय सेमरिया, गोविंदगढ़ व देवतालाब भी 2एफ, 12बी की मान्यता से विहीन है। नईगढ़ी महाविद्यालय का अपना भवन इसी वर्ष बना तो है लेकिन आवेदन कार्यवाही पूरी न होने से इस महाविद्यालय को भी 2एफ और 12बी की मान्यता नहीं मिली है। इस फेहरिस्त में एक और नया नाम नष्टिगवां कॉलेज का जुड़ गया है।

यूजीसी से नहीं मिल रही आर्थिक मदद

बताते हैं कि इन महाविद्यालयों को आज तक यूजीसी से किसी तरह का अनुदान भी नहीं मिला। चूंकि संबंधित महाविद्यालयों के पास 2एफ और 12बी की मान्यता नहीं है, इसलिए यूजीसी से संबंधित महाविद्यालयों को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही। इधर वर्षों से इन महाविद्यालयों को राज्य शासन की ओर से भी ठेंगा ही मिला है।

सीधी के 2 महाविद्यालयों को 2एफ की मान्यता नहीं

सीधी जिले में 8 सरकारी महाविद्यालय बचे हैं। इनमें से 2 महाविद्यालयों के पास स्वयं का भवन न होने के कारण 2 एफ की मान्यता नहीं है। इनमें शासकीय महाविद्यालय सिंहावल व कुसुमी महाविद्यालय का नाम उल्लेखनीय है। मूलभूत सुविधा न होने के कारण ही सीधी के ही सरकारी विधि महाविद्यालय की मान्यता बीसीआई ने रद्द कर दी। फिर भी विभाग ने उक्त महाविद्यालय की व्यवस्था सुधारने से मुंह मोड़ रखा है।

छात्रों को तंबाकू से बचाने के लिए 'टूलकिट' लॉन्च

नईदिल्ली | विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किशोरों को तंबाकू की लत से बचाने के लिए शुक्रवार को एक नया टूलकिट लॉन्च किया। इसे 13 से 17 वर्ष के स्कूली छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 5 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का क्विज आदि शामिल हैं।

परीक्षा • विद्यार्थियों ने प्रभारी तहसीलदार को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, अफसर बोले- जनरल प्रमोशन नहीं, परीक्षा देकर उत्तीर्ण होना जरूरी, घबराएं नहीं सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा का रखा जाएगा ध्यान

विद्यार्थियों ने कहा-हम एक कागज के टुकड़े के कारण अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे

भास्कर संवाददाता | बड़वाह

स्थानीय जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय के अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं देने के निर्णय को गलत बताते हुए विद्यार्थियों ने मोर्चा खोला। 29 जून से 31 जुलाई तक फायनल ईयर की परीक्षा कराने का निर्णय की खबर सुन विद्यार्थियों में आक्रोश है। विद्यार्थी इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुरक्षा की दृष्टि व अलग-अलग परेशानियां लिख कर पोस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है इस महामारी में हमारी परीक्षा को आगे पढ़ाया जाए या हमें जनरल प्रमोशन दिया जाए। एक कागज के टुकड़े के लिए हमारी जान को जोखिम में नहीं डालेंगे।

शुक्रवार को स्थानीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर विद्यार्थियों से हस्ताक्षर कराए। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों ने कार्यालय पहुंच कर प्रभारी तहसीलदार राहुल चौहान को मुख्यमंत्री के नाम आवेदन सौंपा। प्रभारी तहसीलदार ने कुछ ही घंटे पहले खरगोन से बड़वाह तहसील कार्यालय पहुंच कर पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने विद्यार्थियों की समस्या को सुन कर उन्हें पहले तो समझाइश दी कि जनरल प्रमोशन जरूरी नहीं है। आप पढ़ाई करके उत्तीर्ण हो यह जरूरी है। आपकी जब भी परीक्षा होगी घबराएं नहीं, सभी विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों को लगनता के साथ पढ़ाई में जुटे रहने की बात कह कर उनके आवेदन को मुख्यमंत्री को भेजने की बात कही। इसके बाद विद्यार्थियों ने प्राचार्य डॉ. मंगला ठाकुर के निवास स्थान पर पहुंच कर उन्हें भी आवेदन सौंपा। इस दौरान विद्यार्थी कृष्ण स्टिोले, प्रदीप चोबे, नाना दवाडे, विजय चौधरी, नारायण तटवारे, शिवानी केवट, डिंपल यादव मौजूद थी।

बोल- हमारे मुख्यमंत्री जी भांजे-भांजियों को जनरल प्रमोशन देने के लिए राज्यपाल को नहीं मना पाएं

प्रभारी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते विद्यार्थी।

परीक्षा के समय संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं विद्यार्थी

विद्यार्थियों ने बताया मुख्यमंत्री यदि वर्तमान स्थिति में परीक्षा के समय किसी छात्र-छात्रा व शिक्षक कोरोना वायरस से ग्रसित हुआ तो सभी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी। कुलपति को लगता है कि लाखों बच्चों की परीक्षा लेना आवश्यक है यह तो हमें मान्य है लेकिन जो विद्यार्थियों के माता पिता है उनके एक या दो बच्चे हैं लाखों बच्चे नहीं है अगर किसी विद्यार्थी या शिक्षकों को इस बीमारी से कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी कुलपति की होगी या मप्र सरकार की रहेगी।

80 % विद्यार्थी आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से

विद्यार्थियों ने आवेदन के माध्यम से कहा स्थानीय जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय में 80 प्रतिशत विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं। जो लगभग 50 से 60 किमी निवास कर महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं। इनमें से कोई होस्टल में रहता है कोई किराए के मकान में रहता है। रोजाना बस, टैंपो से महाविद्यालय पहुंचता है। इस समय लॉकडाउन के कारण सभी वाहन बंद है। विद्यार्थी भी अपने घरों में निवास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षा होती है तो विद्यार्थियों को परेशानी होगी। छात्रहित में निर्णय लिया जाए कि स्नातक के प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। जिससे विद्यार्थियों व शिक्षकों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके।

नया शिक्षण सत्र होगा लेट

लॉकडाउन की वजह से कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पूरा शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित होगा। वर्ष 2020-21 में नया शिक्षण सत्र यूजी पीजी के प्रथम व द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर पद्धति के विद्यार्थियों को एक सितंबर से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं यूजी पीजी में प्रथम वर्ष सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नया सत्र एक अक्टूबर से शुरू होगा। मौजूदा सत्र में परीक्षाएं देरी से होने का सीधा असर विद्यार्थियों के अगले शिक्षण सत्र पर पड़ेगा। इसके लिए विद्यार्थियों को मौजूदा शिक्षण सत्र में पिछड़े हुए कोर्स पूर्ण करने के साथ अगले सत्र में भी कम समय में कोर्स को पूर्ण करने की चुनौती से निपटना होगा।

जनरल प्रमोशन की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह का रीएक्शन, बोले-

स्टूडेंट्स का भविष्य तब खतरे में होगा जब उनकी परीक्षा रद्द कर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा

भास्कर न्यूज़, भोपाल | विश्वविद्यालय और कॉलेज के कई स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के माध्यम से जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को एक के बाद एक 6 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा है कि परीक्षा की जो तारीखें दी गई हैं, वे इसी बात को ध्यान में रखकर दी गई हैं कि कोई भी छात्र को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो। उनका भविष्य तभी खतरे में होगा जब उनकी परीक्षा रद्द कर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश के भांजे-भांजियों की सबसे ज्यादा चिंता उन्हें है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन हमने भी चुनौती को अवसर में बदलने का निर्णय लिया है। सीएम में कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार छात्रों को कोविड-19 का डर दिखाकर जनरल प्रमोशन की मांग करने के लिए बरगला रहे हैं।

शिक्षा और परीक्षा दोनों महत्वपूर्ण हैं...

सीएम ने कहा है कि छात्रों और अभिभावकों को सोचना चाहिए कि शिक्षा और परीक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग छात्रों का फायदा उठाकर राजनीति से प्रेरित अभियान चला रहे हैं, आपको इन बातों में नहीं आना है।

छात्रों की मांग पर मुख्यमंत्री ने किए एक के बाद एक 6 ट्वीट, बोले-

जनरल प्रमोशन से खतरे में पड़ सकता है छात्रों का भविष्य

भोपाल| विश्वविद्यालय व कॉलेज के कई स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के माध्यम से जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को एक के बाद एक 6 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा है कि परीक्षा की जो तारीखें दी गई हैं, वे इसी बात को ध्यान में रखकर दी गई हैं कि कोई भी छात्र को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो। उनका भविष्य तभी खतरे में होगा, जब उनकी परीक्षा रद्द कर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। छात्रों की परीक्षा न लेकर और जनरल प्रमोशन देकर उनका आगे का जीवन बर्बाद नहीं किया जा सकता। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता लगातार छात्रों को कोविड-19 का डर दिखाकर जनरल प्रमोशन की मांग करने के लिए बरगला रहे हैं। छात्र को आगे बढ़ने के लिए उच्च शिक्षा की जरूरत होती है।

कोरोना से मृत्युदर कम करना है : सीएम

भोपाल|कोरोना से मृत्युदर को कम करना है। इलाज में जरा भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना डेथ एनालिसिस करते हुए कही। सीएम ने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज इंदौर के डीन व चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ कोरोना से वहां हुई मृत्यु का विस्तृत विश्लेषण किया। एसीएस, स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मृत्युदर 4.3% है, जबकि देश की मृत्युदर 2.8% है। प्रदेश में एक्टिव प्रकरणों में भी कमी आई है।

कमिश्नर ने दो प्रभारी प्राचार्यों को दिया वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस

रीवा(नव स्वदेश)। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने सतना जिले के दो तत्कालीन प्रभारी प्राचार्यों को दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है। नोटिस शा.उ.मा.वि. मुकुन्दपुर के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य रामनरेश शर्मा (वर्तमान में शा.बालक उ.मा.वि. कोठी के जिला सतना के व्याख्याता) तथा शा.उ.मा.वि. मुकुन्दपुर के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सतीश त्रिपाठी को जारी किया गया है। नोटिस का जवाब 10 दिनों के भीतर नहीं देने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। जारी नोटिस के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना द्वारा व्याख्याता रामनरेश शर्मा की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई थी। तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सतीश त्रिपाठी ने व्याख्याता रामनरेश शर्मा की रोकी गई वेतन वृद्धि को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं कराई। प्रभारी प्राचार्य द्वारा सहकर्मी साथी को गलत लाभ देने के उद्देश्य से तथ्यों को छुपाकर कूटरचना करते हुए वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की गई। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के इस कृत्य को घोर कदाचरण मानते हुए उन्हें दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है। इसी प्रकरण में कमिश्नर डॉ. भार्गव ने शा.उ.मा.वि. मुकुन्दपुर के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य रामनरेश शर्मा (वर्तमान में शा.बालक उ.मा.वि. कोठी के जिला सतना के व्याख्याता) को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है। श्री शर्मा स्वयं संस्था के प्रभारी प्राचार्य रहे लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना द्वारा रोकी गई एक वेतन वृद्धि के आदेश की प्रविष्टि आपकी सेवा पुस्तिका में नहीं पायी गई। इसे छुपाकर कूट रचना करते हुए वरिष्ठ कार्यालयों के आदेशों की स्वहित लाभ में अनदेखी की गई। साथ ही प्रभारी प्राचार्य रहते समय की वेतन वृद्धि आपके द्वारा स्वयं अपनी सेवा पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 103 में स्वीकृत कर प्रविष्टि की गई जबकि प्रभारी कार्यकाल की वेतन वृद्धियां एवं अन्य लाभ आपके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से स्वीकृत होने चाहिए थे। इन्हीं गंभीर कदाचरण कृत्यों के लिए श्री शर्मा को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया गया है।

प्रभारी उपयंत्री को वेतन वृद्धियां रोकने नोटिस जारी

रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने सतना जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड मझगंवा के प्रभारी उपयंत्री एवं सहायक यंत्री पीसी खरे को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है। नोटिस का जवाब 10 दिवस के भीतर नहीं देने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। जारी नोटिस के अनुसार 18 मई को रीवा संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा के लिए संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कार्यपालन यंत्री सतना द्वारा अवगत कराया गया कि श्री खरे अपने निर्धारित मुख्यालय में नहीं रहते हैं तथा फोन भी यदाकदा ही रिसीव करते हैं। इससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा शिकायतों का निराकरण नहीं हो पाता है। बैठक दिवस से पूर्व सतना जिले के ग्राम किटहा की नलजल योजना एक सप्ताह से मोटर पंप खराब होने के कारण बंद थी जबकि योजना नवीन सृजित हुई है। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने प्रभारी उपयंत्री एवं सहायक यंत्री के इन कृत्यों को गंभीर कदाचरण मानते हुए तथा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर उन्हें दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है।

सरकार ने निजी स्कूलों की मान्यता एक साल के लिए बढ़ाई

भोपाल

सरकार ने निजी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की मान्यता एक साल के लिए बढ़ा दी है। इनकी मान्यता 31 मार्च को खत्म हो गयी थी। लॉकडाउन के कारण मान्यता का काम अधूरा पड़ा था। इनकी परेशानी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आप ही इन स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है।

लॉकडाउन के कारण सरकारी और निजी स्कूल पूरी तरह से बंद हैं। स्कूल बंद होने के कारण निजी स्कूलों की मान्यता भी लंबे समय से अटकी हुई थी। स्कूल संचालकों ने स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता आगे बढ़ाने की मांग की थी। लॉकडाउन के कारण परेशानी को देखते हुए विभाग ने इनकी मांग मान ली। स्कूलों को एक साल की छूट दी है।

जरूरी शर्तें पूरी करना होंगी

मान्यता बढ़ाने के साथ स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को आवश्यक निर्देशों और शर्तों का पालन करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। स्कूलों को हिदायत है कि वो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और 2011 की सभी शर्तों का पालन करेंगे। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विवि की फाइनल ईयर की परीक्षा 29 जून से कराने की तैयारी

कोरोना के बीच परीक्षा, विद्यार्थियों में आक्रोश, कहा-पूरा नहीं हुआ सिलेबस

हरिभूमि न्यूज ▶▶ संतनगर

देश में कोरोना महामारी का रूप लेता जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा 29 जून से कराने के लिए तैयारी कर रही है, जिसे लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश फैला हुआ है। सबसे अहम बात तो यह है कि प्रदेश में अभी तक कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है फिर भी सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों की परीक्षा लेने का निर्णय इतनी जल्दी कैसे कर दिया। इससे तो छात्राओं की जान जोखिम में चली जाएगी।

सरकार द्वारा परीक्षा का निर्णय तो ले लिया गया, लेकिन कॉलेजों में अभी तक छात्रों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, तो कम समय में विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। छात्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि विश्वविद्यालीय परीक्षा होने वाली है तब से छात्रों में मायूसी व आक्रोश छाया हुआ है।

कोरोना से कई लोग हो चुके हैं प्रभावित

इस समय परीक्षा होने से कई प्रकार की समस्या आ सकती है। इसलिए इस विषय पर विचार होना जरूरी है। क्योंकि कोरोना से काफी लोग भयभीत व प्रभावित हुए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में परीक्षा का होना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं होगा।

अमन कौशिक, विद्यार्थी

पुनः विचार करे विवि

सरकार को विवि परीक्षा लेने पर पुन: विचार करना चाहिए। कोरोना वायरस का संक्रमण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी विद्यार्थियों के लिए जनरल प्रमोशन सबसे उचित निर्णय होगा।

शुरत जैन, फर्स्ट ईयर छात्र

जनरल प्रमोशन देना उचित

सरकार द्वारा परीक्षा करवाने पर बहुत ही जल्द फैसला लिया गया। परीक्षा के दौरान कोई बच्चा कोरोना से संक्रमित निकला तो क्या उसके लिए जिम्मेदार सरकार एवं विश्वविद्यालय होंगे। परीक्षा करने के बजाय विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देना ही उचित होगा।

सोहन मेवाड़ा, फाइनल ईयर छात्र

नहीं होनी चाहिए परीक्षा

जब प्रदेश में सामान्य स्थिति हो जाए तभी ही परीक्षाएं ली जानी चाहिए। अभी भी कई विद्यार्थी कंटेनमेंट एरिया में फंसे हुए हैं वह कैसे बाहर निकल कर परीक्षा देने आएंगे। अभी संक्रमण रुका नहीं है इसलिए परीक्षा नहीं होनी चाहिए।

हरीश सिंगरोली, फर्स्ट ईयर छात्र

कंटेनमेंट जोन में स्थित कक्षा 12वीं के तीन परीक्षा केन्द्र बदले गए

कलेक्टर ने जारी किया आदेश, नए परीक्षा केन्द्रों में व्यवस्था करने के निर्देश

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर | कंटेनमेंट जोन में स्थित कक्षा 12वीं के तीन परीक्षा केन्द्रों को बदल दिया गया है। उनकी जगह नए परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। कलेक्टर ने शुक्रवार को परीक्षा केन्द्र बदले जाने का आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। नए परीक्षा केन्द्रों में माशिमं की गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर भरत यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 9 से 15 जून तक 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जानी है। जिले में 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए कुल 104 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जिनमें से तीन परीक्षा केन्द्र कंटेनमेंट जोन में आ गए हैं। बाबू मनमोहन दास हितकारिणी कन्या उमावि शाला दीक्षितपुरा की जगह गुरुनानक उमावि प्रेमनगर, हुसैनिया कन्या उमावि बहोराबाग की जगह नवीन विद्या भवन नेपियर टाउन और हितकारिणी उमावि दमोहनाका की जगह स्माल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्देवबाग को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।

परीक्षा के पहले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग

माशिमं की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि परीक्षा के पहले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। यदि किसी का तापमान बढ़ा हुआ मिलता है तो शासन के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के दौरान छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। परीक्षा केन्द्रों को दो बार सेनिटाइजेशन कराया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी और इनमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। पी-2

राजपत्रित अधिकारी संघ ने मांगी सातवें वेतनमान की दूसरी किश्त

सतना, (नव स्वदेश)। मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ की जिला शाखा द्वारा सातवें वेतनमान के एरियर की द्वितीय किस्त के एरियर भुगतान अतिशीघ्र कराने की मांग की गई है। संघ के अध्यक्ष डॉ. एस.एस. तोमर ने किश्त भुगतान में 1 वर्ष का विलम्ब करने वाले कर्मचारियों की जांच कराकर कार्रवाई किये जाने की मांग कलेक्टर से की है।

म.प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, सतना के अध्यक्ष डॉ. एस.एस. तोमर ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि म.प्र. के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर की राशि का भुगतान तीन किस्तों में करने के निर्देश दिए गये थे। द्वितीय किस्त मई 2019 में भुगतान की जानी चाहिए थी। सभी विभागों में जहां तीसरी किस्त के भुगतान की तैयारी की जा रही है, वहीं कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को द्वितीय किस्त का भुगतान विभागीय लापरवाही की वजह से अभी तक नहीं हो पाया है। लगभग 1 साल लेट हो चुका है, जिसमें जी.पी.एफ. में ब्याज का हजारों रुपये का नुकसान हो चुका है।

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों अधिकारियों की शत-प्रतिशत एरियर भी राशि जी.पी.एफ. में एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत नगदएवं 50 प्रतिशत जी.पी.एफ. में जमा करने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये थे। प्रकरण की जांच कर लापरवाही कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एरियर के भुगतान किये जाने हेतु उचित निर्देश जारी किये जाने की अपेक्षा की गई है।

शिक्षकों की राय, परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी शिक्षा जरूरी

लॉकडाउन | बढ़ा ऑनलाइन शिक्षा का महत्व

सिटी रिपोर्टर . सतना

लॉकडाउन के कारण बच्चे घरों में कैद हैं। जो घर पहले बच्चों की शरारतों से चहकते थे। आज उन्हीं घरों ने क्लासरूम की शक्ल ले ली है। लॉकडाउन ने शिक्षा जगत में डिजिटल क्रांति लाने का काम किया है। जब से लॉकडाउन जारी है तब से बच्चे घरों में कंप्यूटर और फोन के सामने बैठे नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आज छात्र घरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ स्कूल एवं कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नए शैक्षणिक स्तर में बच्चों की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए स्टूडेंट्स के साथ जरूरी नोट्स भी शेयर कर रहे हैं।

पढ़ाई का चुना विकल्प

लॉकडाउन के चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद है। लॉकडाउन ने जहां अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। तो वहीं बच्चों की शिक्षा भी इससे प्रभावित हुई है। कोरोना के इस संकट काल में ऑनलाइन शिक्षा मौजूदा समय की जरुरत बन चुकी है। इसके जरिए बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में एक बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा आने वाले समय में एक विकल्प बनकर रह जाएगी या फिर इसे प्रभावी रुप से हमारी शिक्षा व्यवस्था में अपनाया जाएगा।

कम होगा बस्ते का बोझ

इस संबंध में टीचर्स का कहना है कि स्मार्ट शिक्षा की अवधारणा वास्तव में 21वीं सदी के छात्रों के लिए एक वरदान है। प्रौद्योगिकी के जरिए मानव जीवन में हो रहा बदलाव अच्छे के लिए है। इसके जरिए बच्चों के बस्ता से किताब व कापियों का बोझ कम होगा। अधिकतर विषय फिल्मों व एनिमेशन दृश्यों के जरिए पढ़ाए जाएंगे। इससे किसी भी विषय को समझना ज्यादा आसान होगा।

● ऑनलाइन शिक्षा कभी भी वर्तमान शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती, लेकिन वर्तमान परिपेक्ष्य में विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। आज हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और स्कूल, कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं ऐसे में शिक्षा से जोड़ने के लिए यह माध्यम बहुत प्रभावी दिख रहा है।

पीके जैन, प्रोफेसर

● ऑनलाइन माध्यम को विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचने का उचित माध्यम है। ऑनलाइन शिक्षा कभी भी वर्तमान शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती, लेकिन वर्तमान परिपेक्ष्य में विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। स्मार्ट क्लास काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं।

प्रभात गौतम, शिक्षक

● ऑनलाइन शिक्षा और तकनीक के सहारे हम काफी नई चीजें सिख सकते हैं। लेकिन जो मुलभूत बातें स्कूलों में सिखाई जाती है वो हम शायद ही ऑनलाइन शिक्षा के जरिए सीख पाएं। ऑनलाइन शिक्षा उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो नियमित रुप से स्कूलों में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वे अच्छे संस्थानों की ओर से तैयार की गई ऑनलाइन अध्ययन सामग्री किसी वरदान से कम नहीं है।

पीके जडिया, प्राचार्य

दीक्षा एप डाउनलोड कर प्रशिक्षण और पढ़ाई की ऑनलाइन व्यवस्था बनाएं

डीपीसी व डीईओ ने बीआरसी से वीसी कर ऑनलाइन पढ़ाई एप के मामले में 2 दिन में शत प्रतिशत प्रगति नहीं मिलने पर शिक्षकों पर कार्रवाई के दिए संकेत

भास्कर संवाददाता | डही

लॉकडाउन में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई व मीटिंग (वीसी) को लेकर डीपीसी कमल ठाकुर व डीईओ मंगलेश व्यास गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी बीआरसी से चर्चा की। डही बीआरसी मनोज दुबे भी शामिल हुए। सभी को दीक्षा एप व्यवहार में लाने व राज्य शिक्षा केंद्र ने दो दिन में शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने को कहा है। इसके चलते डीपीसी ठाकुर ने ब्लॉकवार सभी शिक्षकों को एप डाउनलोड करने, एप के द्वारा ही प्रशिक्षण व पढ़ाई को लेकर ऑनलाइन व्यवस्था उपयोग में लाने के निर्देश दिए। लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई के संकेत दिए।

ऑनलाइन बैठक में दिए गए निर्देशानुसार सभी प्रधान पाठक एवं अधीनस्थ शिक्षकों को कक्षावार

डीपीसी व डीईओ ने वीसी के माध्यम से बीआरसी को निर्देश दिए।

दर्ज संख्या के अनुसार 50 प्रतिशत पालकों को कक्षावार ग्रुप में जोड़ने का टारगेट दिया है। प्रत्येक शिक्षक को 5-5 फार्म गूगल शीट में बच्चों, पालको से चर्चा कर भरना है। सभी शिक्षकों को दीक्षा एप पर 30 मई को समय 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन, प्रशिक्षण पूर्ण करना होगा। जिन कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुके है वे प्रशिक्षण 2 दिवस में पूर्ण करें। यदि तकनीकी समस्या आ रही है तो अवगत कराने की बात कही। 27 मई को आयोजित राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा धार जिले की डिजिलेप की प्रगति पर असंतोष जताया था। सभी विकासखंडों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले का औसत 30 प्रतिशत बताया गया। जिसमें बच्चें वाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। वास्तविक स्थिति में यह संख्या और कम सामने आई है। इसके लिए जिले के सभी बीआरसी, बीएसी, बीजीसी एवं जनशिक्षकों को विशेष निर्देश दिए है। बीआरसी दुबे ने बताया ऑनलाइन काम करना जरूरी है। नहीं करने पर नॉन ड्यूटी माना जाकर अवैतनिक किया जाएगा।

जनरल प्रमोशन की मांग पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह का रीएक्शन, बोले-

स्टूडेंट्स का भविष्य तब खतरे में होगा जब उनकी परीक्षा रद्द कर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा

भास्कर न्यूज. भोपाल | विश्वविद्यालय और कॉलेज के कई स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के माध्यम से जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को एक के बाद एक 6 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा है कि परीक्षा की जो तारीखें दी गई हैं, वे इसी बात को ध्यान में रखकर दी गई हैं कि कोई भी छात्र को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो। उनका भविष्य तभी खतरे में होगा जब उनकी परीक्षा रद्द कर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश के भांजे-भांजियों की सबसे ज्यादा चिंता उन्हें है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन हमने भी चुनौती को अवसर में बदलने का निर्णय लिया है। सीएम में कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार छात्रों को कोविड-19 का डर दिखाकर जनरल प्रमोशन की मांग करने के लिए बरगला रहे हैं।

शिक्षा और परीक्षा दोनों महत्वपूर्ण हैं...

सीएम ने कहा है कि छात्रों और अभिभावकों को सोचना चाहिए कि शिक्षा और परीक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग छात्रों का फायदा उठाकर राजनीति से प्रेरित अभियान चला रहे हैं, आपको इन बातों में नहीं आना है।

DB STAR BREAKING छात्र ज्यादा और क्लास रूम कम, इसलिए होगा यह बदलाव ताकि नहीं फैले संक्रमण

डीएवीवी में सोशल डिस्टेंसिंग, घटेंगी यूटीडी की 26% सीटें

1664
सीटों पर नहीं होंगे इस बार एडमिशन

4736
छात्र ही इस बार पढ़ सकेंगे टीचिंग डिपॉर्टमेंट में

6400
सीटों पर हुए थे पिछली साल एडमिशन

मेरी शिक्षा

इंदौर • दिनेश जोशी

नए शिक्षा सत्र (2020-21) में डीएवीवी के 32 टीचिंग विभागों में 26 फीसदी सीटें घट जाएंगी। पिछली बार 6400 सीटों पर एडमिशन दिया था। इस बार इनमें से 1664 पर एडमिशन नहीं दिए जाएंगे। यूटीडी में क्लास रूम की कमी है, जबकि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग अब बड़ी जरूरत बन गई है। ज्यादा छात्रों में ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी यह कदम उठा रही है। सरकार और राजभवन इस पर सहमत है। 1964 में अपनी स्थापना के बाद संभवतः पहला मौका है, जब सीटों की संख्या घटाई जा रही है।

पिछले शिक्षा सत्र में सीईटी के कोर्स की 4800 और नॉन सीईटी की 1600 यानी कुल 6400 सीटें थीं। इनमें 2019 में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण लागू करने से बढ़ाई गई 26 फीसदी सीटें (1664) भी शामिल थीं। यानी, इसके पहले वर्ष 2018 में 4736 सीटें थीं। इस बार यूनिवर्सिटी इतनी ही सीटों पर प्रवेश देने की तैयारी कर रही है। हालांकि उसने यह तय नहीं किया है कि छात्रों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा या नहीं, क्योंकि 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला पहले ही हाई कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने उसे बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। इसी को लेकर हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में मामला चल रहा है। ऐसे में अगर दोनों आरक्षण लागू किए तो यूनिवर्सिटी बची हुई सीटों पर ही इसे लागू करेगी।

आठ विभागों के 34 कोर्स के लिए सीईटी

यूनिवर्सिटी में आईआईपीएस, आईएमएस, लॉ, कम्प्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स सहित 32 टीचिंग डिपार्टमेंट हैं। इनमें से पिछली बार 21 विभागों के 61 कोर्स की 4800 सीटों पर सीईटी से एडमिशन होना थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा ही निरस्त हो गई थी। बाद में इन पर मेरिट आधार पर एडमिशन हुए थे। नॉन सीईटी वाले 11 विभागों के 19 कोर्स की 1600 सीटों पर डिपार्टमेंटल टेस्ट से एडमिशन हुए थे। इस बार सीईटी आठ विभागों के 34 कोर्स के लिए ही होना है।

20 से 40% कम बैठ पाएंगे छात्र कक्षा में

पिछले साल छात्र-छात्राओं की 26 फीसदी सीटें बढ़ने के बाद क्लास रूम की भारी कमी हो गई थी। इस बार तो क्लास में 20 से 40 फीसदी छात्र कम बैठ पाएंगे। नए क्लास रूम का अचानक निर्माण संभव नहीं है। ऐसे में और कोई विकल्प नहीं है। प्रोफेसर डॉ. एके सिंह का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ इस बार कोरोना महामारी में जीवन का भी प्रश्न है। इसलिए कम छात्रों को एडमिशन देंगे।

17 हजार ने दी थी पिछली बार सीईटी

यूटीडी के सीईटी और नॉन सीईटी कोर्स में हर साल एडमिशन लेने वाले 30 फीसदी छात्र जयपुर, कोटा, उदयपुर, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, भोपाल और अन्य शहरों के होते हैं। वहीं, लगभग 50% छात्र इंदौर के होते हैं। पिछले साल करीब 17 हजार छात्रों ने आवेदन किए थे। इनमें से 90 फीसदी से ज्यादा ने परीक्षा दी थी। यूनिवर्सिटी एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सहित 20 से ज्यादा एमबीए स्पेशलाइजेशन कोर्स चलाती है। इन पीजी कोर्स के अलावा बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम अकाउंट एंड टैक्स मैनेजमेंट जैसे यूजी कोर्स भी यहां संचालित हैं। सबसे ज्यादा डिमांड बीए एलएलबी, एमबीए एमएस जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स की है।

ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे: आईआईपीएस में छात्र 1900, क्लास रूम 22 ही

यूनिवर्सिटी के आईआईपीएस जैसे विभाग में 1900 छात्र हैं, जबकि क्लास रूम मात्र 22 ही। इसके अलावा आईएमएस में 2000 छात्रों पर 23 और आईईटी में 2100 छात्रों पर मात्र 29 क्लास रूम हैं। एक क्लास में अधिकतम 30 छात्र बैठा सकते हैं। ऐसे में आईपीएस में 22 क्लास रूम में 660 छात्र ही बैठ पाते हैं। यही हाल बाकी विभागों का भी है।

होस्टल में एक रूम में एक विद्यार्थी ही रहेंगे

डीएवीवी के होस्टलों पर भी कोरोना का असर पड़ेगा। अब किसी भी गर्ल्स और बॉयज होस्टल में एक रूम में एक-एक छात्र या छात्रा रहेगी। अब तक हर रूम में दो-दो छात्रा और छात्र रहते आए हैं। यह इसलिए कि हर छात्र अलग-अलग कमरे में रहेगा तो कोरोना संक्रमण का खतरा न के बराबर होगा। रजिस्ट्रार अनिल शर्मा के अनुसार यह व्यवस्था तुरंत लागू की जा रही है। दरअसल, यूनिवर्सिटी के 11 और आईईटी में तीन सहित 14 होस्टल हैं। इनकी क्षमता 1600 छात्रों की है। नई व्यवस्था से अधिकतम 800 से 900 के बीच ही छात्र-छात्राएं इनमें रह पाएंगे।

राजभवन और शासन की सहमति लेकर लागू करेंगे

राजभवन और राज्य शासन की सहमति लेकर एडमिशन संबंधी सारी गाइडलाइन और निर्णय लागू करेंगे। कोरोना संकट में हम हर उस विकल्प पर काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई गुणवत्ता और छात्र व फैकल्टी की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।
– **अनिल शर्मा,** रजिस्ट्रार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी

सीधी बात

डॉ. एके सिंह
सदस्य सीईटी कमेटी

2018 की सीटों के हिसाब से जारी करेंगे विज्ञापन

- **इस बार यूटीडी में सीटों की संख्या कम हो रही है क्या?**
- हां, हमारी इस पर सहमति बन गई है कि 2018 में जितनी सीटें थीं, उन्हीं के हिसाब से विज्ञापन जारी करेंगे।
- **यानी 26 फीसदी सीटें घटाई जाएंगी। ऐसा क्यों?**
- कोरोना संकट के कारण हम ऐसा कर रहे हैं।
- **10 फीसदी आर्थिक और ओबीसी आरक्षण का क्या होगा?**
- शासन का जो भी आदेश होगा, उसे इन सीटों पर लागू करेंगे।

जुगाड़... डिब्बे और गिलास का ले रहे सहारा

स्कूलों में नहीं हैं तराजू और बाट शिक्षक अंदाज से बांट रहे अनाज

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्राइमरी व मिडिल कक्षाओं के छात्रों को मध्यान्ह भोजन के लिए स्कूल से अनाज का वितरण किया जा रहा है। कोरोना की वजह से स्कूलों में भोजन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए छात्रों को गेहूं और चावल दिया जा रहा है, लेकिन अनाज वितरण के लिए जो वजन निर्धारित किया गया है, उसे तौलने के लिए ज्यादातर स्कूलों में तराजू-बाट की व्यवस्था नहीं है। अनाज वितरण 1 मई से 15 जून तक की अवधि का किया जा रहा है। स्कूलों में तराजू न होने से शिक्षक डिब्बे या गिलास से अंदाजन अनाज छात्रों को वितरित कर रहे हैं। हालांकि, कुछ जगह शिक्षकों ने आसपास के लोगों के सहयोग से वेगिंग मशीन की व्यवस्था भी कर ली है। छात्रों को अनाज देने के लिए उन्हें पास की सरकारी राशन की दुकान से गेंहू-चावल लाना पड़ रहा है।

परेशानी...राशन दुकान से लाते हैं गेहूं-चावल

शिक्षकों ने बताया कि ज्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल में आ रही है। कंट्रोल की दुकान से वे गेहूं-चावल लाते हैं। इसमें स्व-सहायता समूह भी मदद करते हैं, लेकिन उनके पास अनाज तौलने की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को 3 किलो 600 ग्राम गेहूं और 4 किलो 300 ग्राम चावल वितरण किया जा रहा है। नमक, तेल-मसाले के लिए मिडिल के छात्रों के खाते में 221 व प्राइमरी के छात्रों खातों में 148 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। शिक्षकों के मुताबिक तराजू न होने की स्थिति में वे संबंधित माप के डिब्बे का उपयोग कर रहे हैं। अगर किसी डिब्बे में दो किलो अनाज आ जाता है तो उससे माप लेकर अनाज दे दिया जाता है। ऐसे में निर्धारित माप में थोड़ा-बहुत अंतर आ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शिक्षक छात्रों के घर भी सीधे अनाज पहुंचा रहे हैं।

जो भी समस्या आ रही है, दूर की जाएगी

शिक्षक अनाज के पैकेट बनाकर दे रहे हैं। हमने दो अधिकारी भी औचक निरीक्षण के लिए लगाए हैं। जहां से अनाज मिलता है वहां जरूर तुलाई की शिकायतें मिली हैं। जो भी समस्या है उसे दूर करवाएंगे।

– **नितिन सक्सेना,** जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल

शिक्षा विभाग • परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थियों को सैनिटाइज्ड किया जाएगा, होम क्वारेंटाइन छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं होकर पूरक दें सकेंगे

माशिमं की 12वीं कक्षा के बचे विषयों की परीक्षा 9 से 15 जून तक होगी

भास्कर संवाददाता | मंदसौर

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हायर सेकंडरी के बचे विषयों की परीक्षा 9 जून से 15 जून तक ली जाएगी। इससे पहले पूरे केंद्र, कक्षों के साथ परीक्षार्थियों को सैनिटाइज्ड किया जाएगा। एक-एक परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जो परीक्षार्थी होम क्वारेंटाइन रहेंगे, वे मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन्हें पूरक परीक्षा में शामिल किया जाएगा।

परीक्षा का समय सुबह 9 से 12 व दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण व लॉकडाउन के चलते परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला शिक्षाधिकारियों को नए दिशा-निर्देश दिए और उनका पालन कराने को कहा। कितने बच्चे कंटेनमेंट क्षेत्रों में हैं, कितने केंद्र रहेंगे, कितने बढ़ाए जाएंगे, इन सभी बिंदुओं पर तैयारियों के बाद फाइल कलेक्टर के पास जाएगी।

5 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल- जिले में 5 हजार से अधिक विद्यार्थी 73 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। डीईओ आर.एल. कारपेंटर ने बताया कि परीक्षा को लेकर हमने तैयारी शुरू कर दी है। जो विद्यार्थी बाहर से परीक्षा देना चाहते हैं उनके ऑनलाइन आवेदन 28 से लेना शुरू हो जाएंगे। ऐसा केंद्र जो कंटेनमेंट एरिया में है, उसे बदला जा सकता है।

परीक्षार्थियों को घर से ही लाना होगा पीने का पानी

परीक्षार्थियों को जो प्रवेश-पत्र दिए जाएंगे वे परीक्षा के दौरान पास का भी काम करेंगे। विद्यार्थी के साथ एक व्यक्ति मान्य रहेगा। रास्ते में पुलिस के रोकने पर विद्यार्थी को प्रवेश-पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा थर्मल स्कैनर स्कूल प्रबंधन को ही खरीदना होगा। परीक्षार्थी पीने का पानी घर से ही लेकर आएंगे। अगर परीक्षा केंद्र पानी पिलाएगा तो वह परीक्षार्थियों को गर्म करके देगा। होम क्वारेंटाइन परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा में बैठाया जाएगा। छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले परीक्षार्थी वापस छात्रावास में आकर पढ़ाई कर परीक्षा दे सकेंगे।

पुराने प्रवेश-पत्र ही परीक्षा के लिए मान्य होंगे- *पुराने प्रवेश-पत्र ही परीक्षा के लिए मान्य होंगे। इन्हें पास भी माना जाएगा। जो परीक्षार्थी कंटेनमेंट क्षेत्रों से होंगे वे परीक्षा दे सकेंगे, जबकि क्वारंटाइन किए गए छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा जिले के प्राचार्यों से सेंटर को लेकर भी सुझाव मंगवाए हैं। - **आर.एल. कारपेंटर,** जिला शिक्षाधिकारी, मंदसौर*

स्कूल खुलने के बाद सर्दी-जुकाम हुआ तो 15 दिन नहीं आ सकेंगे शिक्षक-विद्यार्थी

मंदसौर | लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू होने वाले स्कूलों में अगले एक साल तक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सख्ती रहेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत सर्दी-जुकाम होने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी और शिक्षक के स्कूल आने पर 15 दिन के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। इस दौरान पढ़ाई ऑनलाइन होगी।

यह निर्देश स्कूल खुलने के बाद अगले 1 साल तक लागू रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल में कक्षाएं शुरू होने के बाद जिन शिक्षक या विद्यार्थी को सर्दी-जुकाम आदि की दिक्कत होगी। उन्हें अगले 15-20 दिन स्कूल आने से रोका जाए। ऐसे शिक्षक घर से ही ऑनलाइन क्लास लेंगे। वहीं शिक्षक स्कूल में पढ़ाए गए चैप्टर को ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। विद्यार्थी द्वारा नोटबुक जमा की जाएगी। इसके कुछ घंटों बाद ही शिक्षक उसे छूएंगे। छूने से पहले सैनिटाइज्ड किया जाएगा।

कोरोना पॉजिटिव हो तो खुद स्कूल आना करेंगे बंद- *एचआरडी ने स्कूल के शिक्षकों के लिए भी गाइडलाइन बनाई है। इसमें कहा है कि गले, मुंह, नाक आदि में इंफेक्शन की शिकायत होने पर शिक्षक खुद ही घर से पढ़ाई कराना शुरू करेंगे। अगर किसी शिक्षक को खुद में कोरोना के लक्षण लगें तो वे तुरंत प्राचार्य से संपर्क कर स्कूल आना बंद करेंगे।*

जून में शुरू होंगे एडमिशन- *केंद्रीय विद्यालय में इन दिनों समर वैकेशन चल रहे हैं। हर साल अप्रैल से मई तक केंद्रीय विद्यालय में कक्षाएं संचालित होती हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं लगीं। उधर, जल्द ही यहां के लिए नए एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। जानकारी के अनुसार नए एडमिशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया जून में शुरू हो सकती है।*

कन्या शिक्षा परिसर थांदला की रिक्त सीट के लिए प्रवेश शुरू

थांदला | कन्या शिक्षा परिसर थांदला में रिक्त सीट पर मैरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाना है। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। संस्था की प्राचार्य क्रिस्टीना डोडियार ने बताया हिन्दी माध्यम की इस संस्था में कक्षा सातवीं में 66, आठवीं में 51, दसवीं में 35, ग्यारहवीं में 45 व बारहवीं में 50 सीटें रिक्त है। आवेदक को पिछली कक्षा में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सीटों की पूर्ति मैरिट के आधार पर की जाएगी। आवेदन अधिक होने पर परीक्षा ली जाकर चयन किया जाएगा।

विद्यार्थियों को मौत के मुंह में छोड़ने का फैसला बेहद है गलत

मंडलेश्वर | प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसके बाद भी सरकार ने कक्षा 12 वीं व महाविद्यालय को जनरल प्रमोशन ना देने के फैसले को गलत बताते हुए एनएसयूआई ने पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जनरल प्रमोशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। एनएसयूआई के अध्यक्ष कुलदीप वर्मा ने कोरोना काल में परीक्षा कराए जाने के विरोध में आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा। उन्होंने बताया महामारी के कारण मार्च में होने वाली कक्षा 10 वीं व 12वीं सहित कॉलेजों की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी लेकिन सरकार ने जून माह में कक्षा 12 वीं व कॉलेजों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। जिससे विद्यार्थी परेशान है। विद्यार्थियों से परीक्षा लेने का निर्णय गलत है। परीक्षा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कक्षा 12 वीं व कालेज विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देकर पास करना चाहिए।

सीबीएसई • ऑड-ईवन फार्मूला अपनाने की सलाह, सिलेबस भी किया जाएगा 25 फीसदी तक कम

15 जुलाई बाद खुलेंगे स्कूल, शनिवार को हॉफ डे नहीं होगा

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 15 जुलाई के बाद स्कूल शुरू करने के संकेत दिए हैं। संक्रमण के खतरे से बचने के लिए सीबीएसई ने स्कूल लगाने के प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। खास बात यह कि विद्यार्थियों को ऑड-ईवन पैटर्न पर बुलाने की अनुमति होगी।

के आधार पर बुलाया जाएगा। इस तरह एक विद्यार्थी हफ्ते में तीन दिन स्कूल आएगा। बाकी तीन दिन उसे घर से ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा पहली से 12वीं तक का सिलेबस 25 से 30 फीसदी तक कम किया जा सकता है। शनिवार को हाफ-डे के बजाय पूरे दिन कक्षाएं लगाई जाएंगी।

▪ होमवर्क : हर क्लास में होमवर्क लिखवाने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। होमवर्क नोट कराने के

जाएंगी। इससे जो समय बचेगा उसमें पढ़ाई कराई जाएगी।

▪ शनिवार को भी क्लास : शनिवार को हाफ-डे के बजाय पूरे दिन क्लास लगेगी। अगर अगस्त में स्कूल शुरू होते हैं तो सात महीने में 28 शनिवार आएंगे। फुल-डे क्लास लगने से 3 पीरियड बढ़ेंगे। यानी कुल 84 पीरियड एक्स्ट्रा मिलेंगे।

▪ सामान्य निर्देश : एक सेक्शन के स्टूडेंट्स दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकेंगे। सिलेबस पूरा करने त्योहार और गर्मी की छुट्टियां भी कम की

आने-जाने के पाइंट बनाए जाएंगे। ताकि एक ही समय भीड़ न हो। डेस्क-कुर्सी के बीच भी एक से डेढ़ फीट की दूरी रखी जाएगी। पहले जितनी जगह में दो विद्यार्थी बैठते थे, अब एक बैठेगा।

▪ सैनेटाइजेशन : स्कूल बसों को रोज अंदर-बाहर से सैनिटाइज करना होगा। हर तीसरे दिन पूरा कैंपस सैनिटाइज किया जाएगा। रोज डेस्क-कुर्सी, ब्लैकबोर्ड, डाइस जैसे सामानों को सैनेटाइज किया जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थियों को मास्क पहनना

वे बदलाव जो शिक्षा 2020-21 में देखने को मिलेंगे

सिलेबस : स्कूल जुलाई से खुल सकते हैं। सिलेबस पूरा करने के लिए समय कम मिलेगा। ऐसे में सिलेबस को 25 फीसदी तक कम किया जाएगा। किसी क्लास में अगर गणित के 20 लेसन हैं

शिक्षक बीमा बचत योजना से जुड़े आदेश पर तारीख की गलती मानी विभाग ने

इंदौर। नवीन शिक्षक संवर्ग को समूह बीमा योजना का लाभ देने से जुड़े आदेश के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी गलती मान ली है। अवर सचिव आरके डेकाट ने 27 मई को आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र लिखा है कि आदेश में 27 जुलाई 2020 को 27 जुलाई 2019 ही पढ़ा जाए। उप सचिव ने 22 मई को आयुक्त के नाम आदेश जारी किया था। इसमें शैक्षणिक संवर्ग यानी राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में शामिल किए गए अध्यापकों को समूह बीमा सह बचत योजना-2003 का लाभ देने की बात कही गई है। विभाग ने इस बारे में पूर्व में जारी आदेश का हवाला दिया है। संदर्भित पत्र जारी करने की जो तारीख दी है, वह 27 जुलाई 2020 है। हकीकत में यह पत्र 27 जुलाई 2019 को जारी हुआ था। डीबी स्टार ने यह मामला 24 मई को में प्रकाशित किया था। इसके बाद अफसर गंभीर हुए और अब लोक शिक्षण संचालनालय को सही तारीख के बारे में पत्र लिखा है। पत्र में लिखा कि बीमा सह बचत योजना 2003 का लाभ देने के संबंध में 22 मई को जारी आदेश के संदर्भित पत्र क्रमांक एफ 1-14/2019/20-1 में 27 जुलाई 2020 को 27 जुलाई 2019 पढ़ा जाए।

संकुल केंद्रों में डिजिलेप ग्रुप बनाने की प्रक्रिया शुरू, नोडल शिक्षक नियुक्त

भास्कर संवाददाता | डही

जिला शिक्षा केंद्र धार से प्राप्त निर्देशानुसार डही विकासखंड के संकुल केंद्रों में शालावार डिजिलेप ग्रुप बनाए जाने के बीआरसी मनोज दुबे ने निर्देश जारी किए। इसके लिए संकुलवार नोडल शिक्षक नियुक्त गए हैं। संकुल डही से मनीष पाटीदार, योगेश राठौड़, संकुल गांगपुर से देवेंद्र त्रिवेदी, जोगेंद्र चौंगड़, संकुल धरमराय से मनोज शर्मा संकुल अतरसुमा से विश्राम बघेल, अजय भारद्वाज, संकुल गाजगोटा से रमेश सिसौदिया, संकुल अराड़ा से अनिल चौहान, कैलाश डोडवा, संकुल फिफेड़ा से महेंद्र बघेल, संकुल बड़दा से पवन हम्मड़, संकुल पड़ियाल से नरेंद्र चौधरी नोडल शिक्षक बनाए गए।

बीआरसी दुबे ने बताया नोडल शिक्षक अपने संकुल अंतर्गत शालावार डिजिलेप ग्रुप बनाएंगे। सभी जनशिक्षक नोडल को पूर्ण सहयोग करेंगे। किसी भी तरह के तकनीकी सहयोग के लिए एमआईएस नितेश चौधरी, अनिल चौहान, अजय भारद्वाज से संपर्क करेंगे। नोडल अधिकारी डिजिलेप ग्रुप निर्माण में सही नाम और गूगल रजिस्ट्रेशन का कार्य स्वयं करेंगे। प्रत्येक ग्रुप में संस्था प्रमुख ओर स्कूल के शिक्षक ग्रुप एडमिन रहेंगे तथा पालकों को क्लासवॉर जोड़ेंगे। सभी शिक्षक, बीएसी, बीजीसी, सीएसी अनिवार्यतः प्ले स्टोर से वेबेक्स एप डाउनलोड कर ले। इसके लिए जिले से वरिष्ठ अधिकारी मीटिंग लेंगे।

कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदलेगा

पार्षद नहीं, जनता ही चुनेगी महापौर; बिल मानसून सत्र में

मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का एक और फैसला पलटने जा रही है। महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के बीच से कराने के कांग्रेस सरकार के फैसले को बदला जाएगा। जनता ही महापौर और पार्षदों को चुनेगी। प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है और मुख्यमंत्री नगरीय आवास एवं विकास विभाग के इस प्रारंभिक प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट में यह संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस पर मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यदि किसी वजह से सत्र में देरी हुई तो सरकार अध्यादेश का भी सहारा ले सकती है। उल्लेखनीय है कि मप्र में 1999 से महापौर का चुनाव सीधे जनता यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा था। पिछली कांग्रेस सरकार ने इसमें संशोधन कर अप्रत्यक्ष प्रणाली को मंजूरी दे दी थी।

झारखंड: डिस्टेंसिंग के लिए बगीचे में पढ़ाई

गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा नहीं, इसलिए सरकारी स्कूल के शिक्षक गांव जाकर पढ़ा रहे

भास्कर न्यूज | रांची

लॉकडाउन की वजह से देश भर में स्कूल बंद हैं। ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी हजारों की संख्या में हैं, जिनके पास न तो फोन है, न इंटरनेट। ऐसे में झारखंड के हुसैनाबाद प्रखंड के नावाडीह की सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक विजय कुमार सिंह ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने ऐसे छात्रों को गांव में ही पढ़ाने की योजना बनाई। इसके लिए बगीचे को चुना गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके। वे बताते हैं- अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बच्चों की पढ़ाई पर चर्चा के दौरान शिक्षकों से कुछ अलग तरीके खोजने की बात होती थी। उसी से यह आइडिया आया। रोज 20-20 बच्चों को दो-दो घंटे पढ़ा रहे हैं।

सहयोगी शिक्षक राम प्रसाद प्रजापति बताते हैं कि इवेंट की तर्ज पर कक्षाओं के हिसाब से ग्रुप बनाकर इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हर ग्रुप को अलग-अलग दिन पढ़ाते हैं, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है।

223 में से सिर्फ 10 बच्चे ऑनलाइन

स्कूल के 223 में से सिर्फ 10 बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले पा रहे हैं। यहां सुबह 8 से 10 बजे तक कक्षा चलती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाता है। सभी बच्चों को साबुन से हाथ धुलवाने के बाद प्रार्थना कार्यक्रम से पढ़ाई की शुरुआत की जाती है।

बोर्ड परीक्षा: शहर में अब तक एक भी परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं

डबरा के स्कूल से हटाया जाएगा कोरेंटाइन सेंटर

एजुकेशन रिपोर्टर | ग्वालियर

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकंडरी की दूसरे राउंड की परीक्षा 9 से 16 जून तक संचालित की जाएंगीं। इसके लिए जिले के 92 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर अफसरों ने मंथन शुरू कर दिया है। गुरुवार को परीक्षा केंद्रों की समीक्षा की गई कि कंटेनमेंट क्षेत्र में तो कोई परीक्षा केंद्र नहीं है। समीक्षा के दौरान शहर में तो कोई परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं मिला लेकिन डबरा के उत्कृष्ट स्कूल में कोरेंटाइन सेंटर बनाए जाने की जानकारी मिली थी। इसको लेकर भी डीईओ विकास जोशी ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। आश्वासन मिला है कि अब यहां पर किसी को नहीं रोका जाएगा, इसके साथ ही सेनेटाइज भी कराया जाएगा।

9 जून से आयोजित होने वाली परीक्षा में जिले के 25 हजार छात्र हिस्सा लेंगे। अफसरों की बैठक में इस बात पर भी मंथन किया गया कि परीक्षा के दौरान 92 परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकेगा या फिर परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाने की स्थिति बनेगी। चूंकि परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही हैं इसलिए वैसे ही एक पाली में आधे छात्र रह जाएंगे। इसलिए किसी भी केंद्र पर ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया जा सके।

12वीं बोर्ड : परीक्षा केंद्रों के सेनेटाइजेशन की व्यवस्था हुई या नहीं, 1 जून तक बताएं

सागर | 9 जून से शुरू होने वाली माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार व्यवस्थाएं कर ली गई हैं या नहीं? इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. महेंद्र प्रताप तिवारी ने जिले के सभी सहायक संचालक, बीईओ तथा एक्सीलेंस स्कूलों के प्राचार्यों से 1 जून तक मांगी है। इस संबंध में डीईओ ने शुक्रवार को पत्र जारी किया है। इसमें परीक्षा केंद्रों को सेनेटाइज कराने की व्यवस्था सहित 14 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। डीईओ ने यह निर्देश जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले द्वारा परीक्षा कराने के संबंध में ली गई समीक्षा बैठक के बाद जारी किए हैं।

यह जानकारी देना होगी 1 जून तक

▪ संशोधित परीक्षा टाइम-टेबल की जानकारी परीक्षार्थियों को दे दी या नहीं? ▪ परीक्षा केंद्रों पर सेनेटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था है या नहीं? ▪ परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर या अपनी नाक-मुंह ढंककर परीक्षा देने आने की जानकारी दे दी है या नहीं? ▪ केंद्रों पर सेनेटाइजेशन की व्यवस्था कर ली गई है या नहीं? ▪ सोशल डिस्टेंसिंग से परीक्षा कराने की व्यवस्था कर ली है या नहीं? ▪ केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले केंद्र पर उपस्थित होने की सूचना दे दी है या नहीं? ▪ परिवर्तित परीक्षा केंद्र पर आवश्यकतानुसार परिवहन की व्यवस्था है या नहीं? ▪ कंटेनमेंट एरिया में निवासरत परीक्षार्थियों की स्कूलवार एवं केंद्रवार संख्या कितनी है? ▪ स्कूल बस से जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आते हैं उनकी सोशल डिस्टेंसिंग से बस द्वारा परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था है या नहीं? ▪ अतिसंवेदनशील और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर कलेक्टर प्रेक्षकों को परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना दे दी है या नहीं? ▪ प्राचार्य, केंद्राध्यक्षों एवं वीक्षकों को सूचना दे दी है या नहीं? ▪ पुलिस थाने में रखे प्रश्न-पत्रों का बीईओ, सहायक संचालक ने भौतिक सत्यापन कर लिया है या नहीं?

रिटर्न में दिखेंगे संपत्ति खरीदी जैसे लेन-देन

नई दिल्ली| इनकम टैक्स ऑनलाइन भरना एक जून से बेहद आसान हो जाएगा। इसमें लॉग इन करते ही अब तक जमा टैक्स के अलावा करदाता की ओर से किए गए खास तरह के ट्रांजेक्शन जैसे- जमीन या कार की खरीदी, बैंक में जमा आदि की भी जानकारी सामने आ जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इससे जुड़े नियम गुरुवार को जारी कर दिए। यह बदलाव 1 जून से लागू हो जाएंगे।

DB STAR BREAKING छात्र ज्यादा और क्लास रूम कम, इसलिए होगा यह बदलाव ताकि नहीं फैले संक्रमण

डीएवीवी में सोशल डिस्टेंसिंग, घटेंगी यूटीडी की 26% सीटें

1664
सीटों पर नहीं होंगे इस बार एडमिशन

4736
छात्र ही इस बार पढ़ सकेंगे टीचिंग डिपॉर्टमेंट में

6400
सीटों पर हुए थे पिछली साल एडमिशन

मेरी शिक्षा

इंदौर • दिनेश जोशी

नए शिक्षा सत्र (2020-21) में डीएवीवी के 32 टीचिंग विभागों में 26 फीसदी सीटें घट जाएंगी। पिछली बार 6400 सीटों पर एडमिशन दिया था। इस बार इनमें से 1664 पर एडमिशन नहीं दिए जाएंगे। यूटीडी में क्लास रूम की कमी है, जबकि कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग अब बड़ी जरूरत बन गई है। ज्यादा छात्रों में ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी यह कदम उठा रही है। सरकार और राजभवन इस पर सहमत है। 1964 में अपनी स्थापना के बाद संभवतः पहला मौका है, जब सीटों की संख्या घटाई जा रही है।

पिछले शिक्षा सत्र में सीईटी के कोर्स की 4800 और नॉन सीईटी की 1600 यानी कुल 6400 सीटें थीं। इनमें 2019 में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण लागू करने से बढ़ाई गई 26 फीसदी सीटें (1664) भी शामिल थीं। यानी, इसके पहले वर्ष 2018 में 4736 सीटें थीं। इस बार यूनिवर्सिटी इतनी ही सीटों पर प्रवेश देने की तैयारी कर रही है। हालांकि उसने यह तय नहीं किया है कि छात्रों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा या नहीं, क्योंकि 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला पहले ही हाई कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने उसे बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। इसी को लेकर हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में मामला चल रहा है। ऐसे में अगर दोनों आरक्षण लागू किए तो यूनिवर्सिटी बची हुई सीटों पर ही इसे लागू करेगी।

आठ विभागों के 34 कोर्स के लिए सीईटी

यूनिवर्सिटी में आईआईपीएस, आईएमएस, लॉ, कम्प्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स सहित 32 टीचिंग डिपॉर्टमेंट हैं। इनमें से पिछली बार 21 विभागों के 61 कोर्स की 4800 सीटों पर सीईटी से एडमिशन होना थे, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा ही निरस्त हो गई थी। बाद में इन पर मेरिट आधार पर एडमिशन हुए थे। नॉन सीईटी वाले 11 विभागों के 19 कोर्स की 1600 सीटों पर डिपॉर्टमेंटल टेस्ट से एडमिशन हुए थे। इस बार सीईटी आठ विभागों के 34 कोर्स के लिए ही होना है।

20 से 40% कम बैठ पाएंगे छात्र कक्षा में

पिछले साल छात्र-छात्राओं की 26 फीसदी सीटें बढ़ने के बाद क्लास रूम की भारी कमी हो गई थी। इस बार तो क्लास में 20 से 40 फीसदी छात्र कम बैठ पाएंगे। नए क्लास रूम का अचानक निर्माण संभव नहीं है। ऐसे में और कोई विकल्प नहीं है। प्रोफेसर डॉ. एके सिंह का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ इस बार कोरोना महामारी में जीवन का भी प्रश्न है। इसलिए कम छात्रों को एडमिशन देंगे।

17 हजार ने दी थी पिछली बार सीईटी

यूटीडी के सीईटी और नॉन सीईटी कोर्स में हर साल एडमिशन लेने वाले 30 फीसदी छात्र जयपुर, कोटा, उदयपुर, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, भोपाल और अन्य शहरों के होते हैं। वहीं, लगभग 50% छात्र इंदौर के होते हैं। पिछले साल करीब 17 हजार छात्रों ने आवेदन किए थे। इनमें से 90 फीसदी से ज्यादा ने परीक्षा दी थी। यूनिवर्सिटी एमबीए मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर सहित 20 से ज्यादा एमबीए स्पेशलाइजेशन कोर्स चलाती है। इन पीजी कोर्स के अलावा बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम अकाउंट एंड टैक्स मैनेजमेंट जैसे यूजी कोर्स भी यहां संचालित हैं। सबसे ज्यादा डिमांड बीए एलएलबी, एमबीए एमएस जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स की है।

ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे: आईआईपीएस में छात्र 1900, क्लास रूम 22 ही

यूनिवर्सिटी के आईआईपीएस जैसे विभाग में 1900 छात्र हैं, जबकि क्लास रूम मात्र 22 ही। इसके अलावा आईएमएस में 2000 छात्रों पर 23 और आईईटी में 2100 छात्रों पर मात्र 29 क्लास रूम हैं। एक क्लास में अधिकतम 30 छात्र बैठा सकते हैं। ऐसे में आईपीएस में 22 क्लास रूम में 660 छात्र ही बैठ पाते हैं। यही हाल बाकी विभागों का भी है।

होस्टल में एक रूम में एक विद्यार्थी ही रहेंगे

डीएवीवी के होस्टलों पर भी कोरोना का असर पड़ेगा। अब किसी भी गर्ल्स और बॉयज होस्टल में एक रूम में एक-एक छात्र या छात्रा रहेगी। अब तक हर रूम में दो-दो छात्रा और छात्र रहते आए हैं। यह इसलिए कि हर छात्र अलग-अलग कमरे में रहेगा तो कोरोना संक्रमण का खतरा न के बराबर होगा। रजिस्ट्रार अनिल शर्मा के अनुसार यह व्यवस्था तुरंत लागू की जा रही है। दरअसल, यूनिवर्सिटी के 11 और आईईटी में तीन सहित 14 होस्टल हैं। इनकी क्षमता 1600 छात्रों की है। नई व्यवस्था से अधिकतम 800 से 900 के बीच ही छात्र-छात्राएं इनमें रह पाएंगे।

राजभवन और शासन की सहमति लेकर लागू करेंगे

राजभवन और राज्य शासन की सहमति लेकर एडमिशन संबंधी सारी गाइडलाइन और निर्णय लागू करेंगे। कोरोना संकट में हम हर उस विकल्प पर काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई गुणवत्ता और छात्र व फैकल्टी की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।

– **अनिल शर्मा**, रजिस्ट्रार देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी

सीधी बात — डॉ. एके सिंह, सदस्य सीईटी कमेटी

2018 की सीटों के हिसाब से जारी करेंगे विज्ञापन

- **इस बार यूटीडी में सीटों की संख्या कम हो रही है क्या?**
  - हां, हमारी इस पर सहमति बन गई है कि 2018 में जितनी सीटें थीं, उन्हीं के हिसाब से विज्ञापन जारी करेंगे।
- **यानी 26 फीसदी सीटें घटाई जाएंगी। ऐसा क्यों?**
  - कोरोना संकट के कारण हम ऐसा कर रहे हैं।
- **10 फीसदी आर्थिक और ओबीसी आरक्षण का क्या होगा?**
  - शासन का जो भी आदेश होगा, उसे इन सीटों पर लागू करेंगे।

कोरोना काल : स्कूल खोलने के लिए नया मॉडल तैयार कर रहा एचआरडी मंत्रालय

नए जमाने की स्कूलिंग, 220 में 100 दिन घर से ऑनलाइन पढ़ाई

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. कोरोना महामारी के चलते आम लोगों की जीवनशैली में बड़े बदलाव सुनिश्चित हैं। ऐसा ही बड़ा बदलाव देश की स्कूली शिक्षा में लाने की तैयारी है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों के मौजूदा 220 शिक्षणदिवस या स्कूलों में 1,320 शिक्षण घंटे के मॉडल को 'स्कूल और घर में मिली-जुली पढ़ाई' से बदलने की तैयारी में है। नए प्रस्तावित मॉडल के तहत स्कूलों में पढ़ने के समय को 100 दिन या 600 घंटे तक कम करके इस समय को 'घरों पर सक्रिय पढ़ाई' में बदल दिया जाएगा। वहीं स्कूलों में भी इतने ही समय यानी 100 दिन या 600 घंटे पढ़ाई होगी। बचे हुए 120 घंटे या 20 दिन (हर माह दो दिन) विद्यार्थियों के भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए स्कूलों या घरों में डॉक्टरों, काउंसलर्स आदि के लिए तय कर दिए जाएंगे।

उपस्थिति — 30-50% बच्चे ही रहेंगे स्कूलों में

एक बार में 30-50% से ज्यादा बच्चे स्कूलों में मौजूद न रहें। इसके लिए शेड्यूल फॉर्मेट या रोटेशनल शिफ्ट को कहा जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक को सप्ताह में केवल 3 दिन और कक्षा 6 से 8 तक बच्चों को सप्ताह में 2 से 4 दिन और कक्षा 9 से 12 तक छात्रों की 4 से 5 दिन कक्षाएं लगेंगी।

पीरियड — 45 मिनट की जगह 30 मिनट

- **साप्ताहिक** टाइम टेबल सिस्टम जिसमें पीरियड का समय 45 मिनट से घटाकर 30 मिनट करने की भी सलाह दी जाएगी।
- **कुछ** विषयों के एकीकृत पढ़ाई के लिए एक घंटे के विशेष पीरियड की योजना भी प्रस्तावित की जा सकती है।

अवकाश — लचीले नियम, घर से पढ़ने की छूट

उपस्थिति की अनिवार्यता और बीमारी के लिए छुट्टी के प्रावधानों को काफी लचीला बनाया जाएगा। इनमें माता-पिता की सहमति से इच्छुक विद्यार्थियों को उचित नियमों के साथ घर से पढ़ने की छूट देना का प्रस्ताव भी शामिल है।

सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एसओपी

स्कूल, कक्षा, स्कूल बस-ऑटो, लैब, खेल के मैदान व अन्य सभी तरह गतिविधियों के दौरान उचित सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी किए जाएंगे।

मूल्यांकन — क्विज और प्रोजेक्ट ज्यादा

सूत्रों के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय पेन और पेपर पर आधारित मूल्यांकन व्यवस्था को हतोत्साहित करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके बजाय कक्षाओं में भूमिका अदा करना, क्विज व प्रजेंटेशन्स और घरों पर प्रोजेक्ट वर्क आदि शामिल हैं।

मिड डे मील — जारी होगी गाइडलाइन

सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए अलग गाइडलाइन जारी होगी। इनमें सब्जियों को नमक-हल्दी के घोल से धोने सहित खाना बनाने वाले व सहायकों की रोजाना थर्मल स्क्रैनिंग और बर्तनों को सैनेटाइज प्रक्रियाएं होंगी।

वंचितों को तरजीह

सभी स्कूलों से ऐसे वंचित बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने को कह सकता है जिनके पास ऑनलाइन सुविधाएं व सीखने के साधन उपलब्ध नहीं।

नहीं काटे जाएंगे नाम

पलायन वाले इलाकों में मौजूद स्कूलों से फौरन ही ऐसे बच्चों को नाम न काटने को कहा जाएगा जो अपने गृहराज्य या गृहजनपद में पलायन कर गए हैं।

स्कूलों में होंगे इंतजाम

- **आउटडोर क्लास:** जहां संभव हो अस्थायी आउटडोर क्लास बनाएं जाएं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
- **6 फुट की दूरी:** क्लास रूम में, स्टाफ रूम, रिसेप्शन आदि में 6 फुट की दूरी।
- **प्रवेश व निकासी :** प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग लेन। निकासी के कई रास्ते होंगे व प्रवेश के सीमित।
- **स्कूल परिवहन:** स्कूल बस आदि की रोज दो बार सैनेटाइजेशन होगा। एक सीट पर एक बच्चा ही बैठेगा। बस में कोई पर्दा नहीं होगा।
- **टाइमटेबल:** कक्षा 1-8 के लिए एसओपीआरटी बनाएगा।
- **स्कूल बैग:** कक्षा 5 के बच्चों को आदर्श रूप में कोई स्कूल बैग नहीं ले जाना होगा।

अच्छी खबर ... जिले में पौने चार लाख स्कूल ड्रेस बनाएंगी महिलाएं, स्व-सहायता समूहों को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम

स्व-सहायता समूह की महिलाओं के बने स्कूल ड्रेस में नजर आएंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे

सतना. जिले की शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाले 1.87 लाख स्कूली बच्चे स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार ड्रेस में नजर आएंगे। अगर सब कुछ सही रहा और कोई बड़ी अड़चन न आई तो जल्द ही ड्रेस बनाने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए एनआरएलएम मिशन से जुड़ी स्व-सहायता समूह की 785 महिलाओं को स्कूली ड्रेस बनाने का पुनः प्रशिक्षण (रिफ्रेशर कोर्स) दिया जा रहा है। इतना ही नहीं जिला पंचायत की ओर से डीएमएफ मद से अत्याधुनिक सिलाई मशीनें भी मंगाई गई हैं, जो संभवतः अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएंगी। कोरोना लॉकडाउन काल में मास्क बनाकर अपने पैरों पर समूह की महिलाओं को खड़ा करने की अभिनव सफल पहल के बाद अब समूह की महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का यह जिपं सीईओ ऋजु बाफना एक और प्रयास है। अगर सफल रहा तो लगभग इससे महिलाओं को लाखों रुपए की आमदनी होगी।

शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दो जोड़ी स्कूल ड्रेस देने का प्रावधान है। इसके लिए अब तक शासन की ओर से बच्चों के खाते में 600 रुपए स्कूल ड्रेस के

लिए डाल दिए जाते थे। इस राशि का कई मामलों उपयोग नहीं होता था तो काफी संख्या में समरूपता नहीं रहती थी। उधर जिपं सीईओ बाफना ने पाया कि स्व-सहायता समूह की महिलाओं को अगर यह काम दे दिया जाए तो वे एक झटके में मुख्य धारा में आ जाएंगी। इसके लिए महिलाओं को एनआरएलएम मिशन के तहत आरसेटी से सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया गया। इधर, इस दिशा में शासन स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं।

20 लाख की अत्याधुनिक मशीनें

जिपं सीईओ ने इस काम के लिए डीएमएफ मद से चार सेंटरों के लिए 20.46 लाख रुपए स्वीकृत कराए थे। इस राशि से अम्बेला मॉडल इलेक्ट्रानिक सिलाई मशीन, इलेक्ट्रानिक कज-बटन मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कटिंग मशीन व इलेक्ट्रॉनिक इन्टरलॉक मशीन का आर्डर हो चुका है। बताया गया कि अगले कुछ दिनों में यह मशीनें आ जाएंगी जिन्हें नागौद व अमरपाटन के चार सेंटरों में स्थापित किया जाएगा। इसका उपयोग करने के लिए समूह की महिलाओं को जिम्मा दिया जाएगा। यहां भी स्कूल ड्रेस बनाए जाएंगे।

16 ट्रेनिंग सेंटर चालू

बताया गया है कि स्कूली ड्रेस बनाने का काम शुरू करने से पहले महिलाओं को जिले के सभी ब्लाक मुख्यालय के 16 रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें काम इस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ समूह सिर्फ शर्ट, कुछ पैंट, कुछ सलवार कमीज बनाएंगे। ताकि, तेजी से ड्रेस तैयार हो सकें। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि ड्रेस के लिए कच्चा माल कहां से और कैसे लिया जाएगा। इन सभी के द्वारा 3.74 लाख स्कूल ड्रेस तैयार किए जाने हैं।

इग्नू ने एग्जाम डेट में किया परिवर्तन, आवेदन 15 तक

भोपाल ◆ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जून के लिए होने वाले टर्म एंड एग्जाम के लिए आवेदन जमा करने की तारीखों में एक बार फिर बदलाव किया है। जून में होने वाली टीईई-2020 के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की तारीख पहले 31 मई थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 जून कर दी गई है। अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म ignou.ac.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इससे पहले भी इग्नू 3 बार आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ा चुका है। इग्नू ने परीक्षा की तारीख की घोषणा नहीं की है।